श्री वीरभद्र सिंह : मैंने उत्तर में बताया है कि 52 व्यक्ति छोड़ कर गये हैं और 84 व्यक्ति आये हैं। कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में सीमेंट कारपोरेशन निरंतर विचार करती है।

श्री जे० के० जैन : उनके बारे में आपने कोई जांच करवाई है या नहीं? और उनके छोड़ कर जाने से सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया को क्या नुकसान हुआ है? इसका मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री वीरभद्र सिंह : जहां तक हमारी जानकारी है कोई ऐसी बात हमारे ध्यान मे नही आई कि जहां पर उनके जाने से सीमेंट कारपोरेशन को कोई नुकसान हुआ हो।

Report on Meerut Riots

*62. SHRI SYED AHMAD HASHMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the U.P. Government have submitted any report to the Central Government on the riots in Meerut; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b) The Government of Uttar Pradesh have sent situation reports. A dispute between the two communities arose over a place of worship. After an incident on 6.9.1982, the situation escalated and disturbances continued almost upto the second week of October, 1982. Those was loss of life and property in these disturbances.

श्री सैयद अहमद हाशमी : सर, यह शुक्र है कि यू० पी० गवर्नमेंट ने रिपोर्ट भेजी। जबकि उसमें जो बहुत बड़ा अहम मसला था पी० ए० सी० के रोल का और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल का, इसकी उसमें कुछ तफसील नहीं है। लेकिन यहां इस सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं आनरेबल मिनिस्टर से कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर जो बड़े-बड़े फिसादात हुए, सभी का मैं नही कहता लेकिन बहुत से बड़े-बड़े फिसादात के मौकों के ऊपर कमीशन बने। मदन कमीशन, रेड्डी कमीशन, सिन्हा कमीशन, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन की रिकमेंडेशन्स कहीं इम्प्लीमेंट हुई? क्या हुकूमत की निगाह में यह रिकमेंडेशन्स इस काबिल नहीं कि उन पर अमलदरामद किया जाय ताकि कम्युनल रायट्स में कोई कमी हो। आप देखेंगे कि इन कमीशनों के अलावा माइनारिटीज की पूरी सिचुएशन को और कम्युनल रायट्स को सामने रख कर माइनारिटीज कमीशन बना, हाई-पावर माइनारिटी कमीशन बना। हाई पावर कमीशन बना। उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी। इनमें से बाज की रिपोर्ट ही पेश नहीं हुई, और बाज की पेश भी हुई तो उस पर डिबेट या गुफतगु का मौका पार्लियामेंट को नहीं दिया गया। क्या इस तरह के कई कमीशन्स जो बने हैं उन का सिर्फ यही मकसद है कि थोड़ी देर के लिए लोगों को मुतमईन किया जाय डिप्टी चेयरमैन साहब मैं इस लिए यह बात कह रहा हूं कि हम फील करते हैं कि सिसियारिटी के साथ माइनारिटी के बारे में, कम्युनल रायट्स के बारे में हुकूमत सीरियस नहीं है। मैं इसी कम्युनल रायट मेरठ के सिलसिले में अर्ज करता हूं। पिछले दिनों हमारी मोहतरिमा प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ काफी अरसे के बाद। हम सोचते थे कि मजलूम लोगों के पास वह जायेंगी तो उन्हें कुछ तसल्ली हो जायेगी, लेकिन मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि मैं खुद मेरठ गया हूं वहां लोगों से बात करने पर अन्दाजा यह हुआ कि जो

वाकई मजलूम थे वहां तक प्राइम मिनिस्टर का गुजर नहीं हुआ जिससे कि उनके अन्दर सब्र पैदा होता, उनकी तसल्ली होती लेकिन इसके बरकस इनमें बेजारी पैदा हुई है और यह अहसास पैदा हो रहा है कि इतने कमीशन बने, बड़े-बड़े लोगों का दौरा हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी आती हैं लेकिन हमारे जख्म का इलाज होता नहीं। वह क्या चाहते है ? वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें महसूस करा सके कि वह वाकई सीरियसली इस बारे में सोच रही है ?

†[شری سید احمد ہاشمی : سر -

یہ شکر ہے کہ یو - پی - گورنمنٹ نے رپورٹ بھیجی جسمیں جو بہت بڑا اہم مسئلہ تھا پی- اے- سی- کے رول کا اور ایڈمنسٹریشن کے رول کا اسکی اسمیں کچھ تفصیل نہیں ہے - لیکن یہاں اس سلسلے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں آنریبل منسٹر سے کہ مختلف موقعوں کے اوپر جو بڑے بڑے فسادات ہوئے سبھی کا میں نہیں کہتا لیکن بہت سے بڑے بڑے فسادات کے موقعوں کے اوپر کمیشن بنے - مدن کمیشن - ریڈی کمیشن - سنہا کمیشن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اکی رکمنڈیشن کبھی امپلیمینٹ ہوئی - کیا حکومت کی نگاہ میں یہ رکمنڈیشن اس قابل نہیں کہ ان پر عمل درآمد کیا جائے تاکہ کمیونل رائٹس میں کوئی کمی ہو - آپ دیکھیں گے کہ ان کمیشنوں کے علاوہ مائنارٹیز کی پوری سچوایشن کو اور کمیونل رائٹس کو سامنے رکھکر مائناریٹیز کمیشن بنا ہائی پاور کمیشن بنا - انہوں نے رکمنڈیشنس بھی دیں - ان میں سے بعض رپورٹ ہی پیش نہیں ہوئی - اور بعض کی پیش ہوئی تو اس پر ڈبیٹ یا گفتگو کا موقعہ پارلیمنٹ کو نہیں دیا گیا - کیا اسطرح کے کئی کمیشنس جو بنے ہیں انکا صرف یہی مقصد ہے کہ تھوڑی دیر کیلئے لوگوں کو مطمئن کیا جائے - ڈپٹی چیرمین صاحب میں اسلئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ سنسیرٹی کے ساتھ مائناریٹیز کے بارے میں - کمیونل رائٹس کے بارے میں حکومت سیریس نہیں ہے - میں اسی کمیونل رائٹ میرٹھ کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں - پچھلے دنوں ہماری محترمہ پرائم منسٹر کا دورہ ہوا کافی عرصہ کے بعد - ہم سوچتے تھے کہ مظلوم لوگوں کے پاس وہ جائیں گی تو انہیں کچھ تسلی ہو جائے گی - لیکن مجھے تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں خود میرٹھ گیا ہوں وہاں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ جو واقعی مظلوم تھے وہاں تک پرائم منسٹر کا گزر نہیں ہوا جس سے کہ ان کے اندر صبر پیدا ہوتا - ان کی تسلی ہوتی لیکن اس کے برعکس ان میں بیزاری پیدا ہوئی

†Transliteration in Arabic Script

ہے - اور یہ احساس پیدا ہو رہا ہے
کہ اتنے کمیشن بنے - بڑے بڑے لوگوں
کا دورہ ہوا - پرائم منسٹر بھی آئی
ہیں - لیکن ہمارے زخم کا علاج نہیں
ہوا - وہ کیا چاہتے ہیں - وہ
صرف اتنا چاہتے ہیں کہ حکومت
انہیں محسوس کرا سکے وہ واقعی
سیریس ہی اس بارے میں سوچ
رہی ہے -]

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Sir, since he has referred to me, I think I should reply. जब मैं मेरठ गयी तो जितने लोगों ने मोटर रोकी, चाहे ग्रुप, चाहे कागज देना चाहते थे या ऐसे ही रोका, हर जगह रुककर मैंने बात की। इत्तिफाक से जिस जगह का यह जिक्र कर रहे थे वहां कोई बाहर नहीं था, किसी ने नहीं कहा यहां रुकना है या इस घर के अन्दर लोग है। जब मैं वापस हेलीकोप्टर में बैठ गई तब कोई दौड़े-दौड़े आये कि यह नहीं हुआ है। उस वक्त जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन उस वक्त यह तय हुआ कि वहां कुछ औरते थीं वह मुझसे मिलने लाई जायेंगी। लेकिन पार्लियामेंट फौरन शुरू हो गई और मैं आसाम चली गयी, इसलिये उसमें देर हुई। लेकिन मुझे जरा भी झिझक नहीं है उनसे मिलने की। उनकी तकलीफ की कहानी मैं पहले भी सुन चुकी हू। उनमें से बहुत सी औरतें आ भी चुकी हैं पहले, लेकिन फिर से उन्हें लाने को जो हमारे एम० पी० है वहां के उनसे मैंने कहा है।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: One thing I would like to say and that is, when my friend says that the Government is not serious about such situations, I would like to say that it is a totally wrong thing to say. The Government is really serious about those problems and that is why the Home Minister visited, the Prime Minister herself visited all these places, and it is under control now.

श्री सैयद अहमद हाशमी : कई चीजों का आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा है कि सिर्फ एक यू० पी० गवर्नमेंट की रिपोर्ट की बात नहीं है, आलरेडी इतने फसादों के अन्दर कमीशन बने, उनका कमीशन्स का क्या मतलब था और इनका क्या फायदा हुआ ?

†[شری سید احمد ہاشمی : کئی
چیزوں کا آنریبل منسٹر صاحب نے
جواب نہیں دیا - میں نے پوچھا ہے
کہ صرف ایک یو - پی - گورنمنٹ
کی رپورٹ کی بات نہیں ہے - الریڈی
اتنے فسادوں کے اندر کمیشن بنے -
ان کمیشنوں کا کیا مطلب تھا اور
ان کا کیا فائدہ ہوا -]

श्री उपसभापति : आप सिर्फ मेरठ के बारे में पूछिये। बहुत लम्बा चौड़ा जवाब नहीं हो पायेगा।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मेरे कहने का मतल है कि f तने फसादों के सिलसिले में कमीशन बने इनका नतीजा क्या निकला, मेरठ रायट सिर्फ एक नहीं है, आज भी सिचुएशन वही है...

†[شری سید احمد ہاشمی : میرے
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فسادوں
کے سلسلے میں کمیشن بنے ان کا
نتیجہ کیا نکلا - میرٹھ رائٹ صرف
ایک نہیں ہے - آج بھی سچوایشن
وہی ہے -]

श्री उपसभापति : सवाल दूसरा पूछिये

श्री सैयद अहमद हाशमी : मेरा सवाल यही है और बहुत साफ है। मैं इस पर जोर दूंगा। इतने कमीशन बने, इनका क्या हुआ। फसादात के सिलसिले का यह

†Transliteration in Arabic Script

हिस्सा है । अगर हुकूमत सीरियस होती तो इतने कमीशन्स बनें, उन की रिपोर्ट पर अमल होता । इसके ताल्लुक से चाहूंगा कि मंत्री जी मुझे जवाब दें ।

†[شری سید احمد هاشمی : میرا سوال یہی ہے اور بہت صاف ہے - میں اس پر زور دوں گا - اتنے کمیشن بنے ان کا کیا ہوا - فسادات کے سلسلے کا وہ حصہ ہے - اگر حکومت سیریس ہوتی تو اتنے کمیشنس بنے - ان کی رپورٹس پر عمل ہوتا - اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ منتری جی مجھے جواب دیں ۔]

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : डिप्टी चेयरमैन साहब, यह जो कमीशन आफ इंक्वायरी इस सिलसिले में बनी हैं उन की रिकमेंडेशन्स के बारे में पूरी बहस के पश्चात् कुछ गाइड लाइन्स बना कर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गयी हैं और जैसा उस रोज दूसरे हाउस में बताया इस सिलसिले में, हाल ही में जो नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग हुई थी उस के पश्चात् स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पी ए सी और इस प्रकार के जो दूसरे फोर्सेज हैं, आर्म्ड फार्सेज उन को रिआर्गनाइज करने के लिए पत्र लिखा है । यह पत्र हाल ही में 18 जनवरी, 1983 को लिखा गया है और इस के अलावा हर जगह पीस कमेटीज और इंटीग्रेशन कौंसिल बनाने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा गया है । जो ऐसे जिले हैं जहां आम तौर पर इस तरह के फसादात होते रहते उन की मुकम्मिल सूची स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजी गयी है और वहां यह हिदायतें दी गयी हैं कि यहां पर खास तौर से तवज्जह दी जानी चाहिये । इस के अलावा उन राज्यों को जहां आम तौर पर यह फसादात होते रहते हैं, जैसे यू० पी० है, बिहार है, महाराष्ट्र है या गुजरात है, उनको यह भी लिखा गया है कि एक स्टेडी ग्रुप उन को बनाना चाहिये जो इनके कारणों में जाय और मुख्तसर में जो उसके कारण हैं उन में जाय और उसके पश्चात् उन का इलाज ढूंढे और उस पर अमल करे ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : अभी तो 1983 को शुरुआत है । पता नहीं पूरे साल में क्या होगा, लेकिन लोक सभा के अन्दर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो फीगर्स दिये हैं फसादत के सिलसिले में 1980, 1981 और 1982 के, उन में 1980 में 427...

†[شری سید احمد هاشمی : ابھی تو ۱۹۸۳ کی شروعات ہے - پتہ نہیں پورے سال میں کیا ہو گا - لیکن لوک سبھا کے اندر ہمارے منسٹر صاحب نے جو فیگرس دیئے ہیں فسادات کے سلسلے میں ۱۹۸۰-۱۹۸۱ اور ۱۹۸۲ کے - ان میں ۱۹۸۰ میں ۴۲۷.....]

श्री उपसभापति : यह सवाल तो इससे नहीं उठता । इसे आप कालिंग अटेंशन में उठाइयेगा । अभी तो आप सिर्फ मेरठ के बारे में सवाल पूछें ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : यह कोई मेरठ शहर के बारे में ही सवाल नहीं है । यह तो कम्युनल फसादात के मुताल्लिक सवाल है । मैं यह अर्ज करूंगा कि इसका पूरा जवाब दिया जाये ।

†Transliteration in Arabic Script

†[شری سید احمد ہاشمی : یہ کوئی میرٹھ شہر کے بارے میں ہی یہ سوال نہیں ہے - یہ تو کمیونل فسادات کے متعلق سوال ہے میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا پورا جواب دیا جائے -]

श्री उपसभापति : यह आप मेरठ के बारे में ही सवाल पूछिये ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : अभी 1983 की शुरुआत है । आनरेबल होम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक 1982 में जितने फसादात हुये हैं उनको देखते हुये उसको रायट-इयर, फसादात का साल कहा जा सकता है। मैं इस सिलसिले में पूछना चाहता हूं कि आखिर इन फसादात में पहले के मुकाबले में इतना इजाफा क्यों हुआ है और अगर है तो फिर वही सवाल उठता है कि क्या यह इसलिये नहीं कि फसादात का करेक्टर पहले के मुकाबले में चेंज हो गया है। पहले फसादी हमला करते थे। अक्सर पुलिस जानिबदारी भी करती थी, लेकिन उस का एक रोल होता था । लेकिन क्या यह शक्ल नहीं है आज कि पी० ए० सी०, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सब उसमें इन्वाल्व है और उनका इन्वाल्वमेंट रहता है । बजाय इसके कि उनका कन्डमनेशन हो, उनकी मजम्मत हो, लेकिन हुकूमत उनको डिफेंड करती है । चुनाचे मेरठ के रायटस में भी यही हुआ बजाय इसके कि पी० ए० सी० के रोल पर वहां के फसादात के सिलसिले में उन पर कोई प्रापर एकशन होता, वहां के मुलजिमान को सजा दी जाती या वहां के कमिश्नर को सस्पेंड किया जाता, इसके बजाय हुकूमत की तरफ से उन को डिफेंड किया गया । यह आखिर जो शक्ल है क्या यह वजह नहीं है इन फसादात में इजाफा होने का ?

†[شری سید احمد ہاشمی : ابھی ۱۹۸۳ کی شروعات ہے - آنریبل ہوم منسٹر کے کہنے کے مطابق ۱۹۸۲ میں جتنے فسادات ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو رائٹس فسادات کا سال کہا جا سکتا ہے میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان فسادات میں پہلے کے مقابلے میں اتنا اضافہ کیوں ہوا ہے اور اگر ہے تو پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ اس لئے نہیں کہ فسادات کا کریکٹر پہلے کے مقابلے میں چینج ہو گیا ہے - پہلے فسادی حملہ کرتے تھے - اکثر پولیس جانبداری بھی کرتی تھی - لیکن اس کا ایک رول ہوتا تھا - لیکن کیا یہ شکل نہیں ہے آج کہ پی - اے - سی - ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس سب اس میں انوالو ہیں - اور ان کا انوالومینٹ رہتا ہے - بجائے اس کے کہ اس کا کنڈم نیشن ہو - ان کی مذمت ہو - لیکن حکومت ان کو ڈفینڈ کرتی ہے - چنانچہ میرٹھ کے رائٹ میں بھی یہی ہوا - بجائے اس کے کہ پی - اے - سی - کے رول پر وہاں کے فسادات کے سلسلے میں کوئی پراپر ایکشن ہوتا - وہاں کے ملزمان کو سزا دی جاتی یا وہاں کے ایڈمنسٹریشن کو سسپینڈ کیا جاتا -

اس کے بھائی حکومت کی طرف سے
ان کو ڈیفینڈ کیا گیا - یہ آخر جو
شکل ہے کیا یہ وجہ نہیں ہے ان
فسادات میں اضافہ ہونے کی -]

SHRIMATI INDIRA GANDHI: It is very unfortunate, if I may say so. The honourable Member's remarks are unfortunate because we have condemned any kind of wrong doing. What action has been taken, the honourable Minister of Home Affairs will say. But if you keep on condemning the police or the PAC, it does not create a more peaceful atmosphere not only in that place but in other places. either on this side or that side of the If we want to defend people in all places, we have to see that we do not alienate these forces. If there is a guilty person, then there is no one, either on this side or that side of the House, who wants that person to be shielded. He must be punished. There is absolutely no doubt about it. But wholesale condemnation of the whole force is not good. I have heard myself that this creates dissatisfaction or disaffection among them in other places and they may feel: 'If we are not trusted, we won't do the job'. I want the hon. Member to be very care ful in choosing his words in such very delicate situations.

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक यू० पी० में आफिसर्स का सवाल है यू० पी० गवर्नमेंट ने, मेरठ के जिन एक, दो अफसरों के खिलाफ शिकायत की थी, उनको तुरन्त वहां से हटाया । पी० ए० सी० के बारे में भी शिकायत थी इसीलिए सेन्टर मे सी० आर पी एफ० को स्पेशल तीन बटेलियन बनाई गई हैं वह भेजी गई । इसके अलावा बी० एस० एफ० की दूसरी बटेलियन भेजी गई । बी० एस० एफ० की बटेलियन भेजी गई । आज भी मेरठ में सी० आर पी एफ० की तीन बटेलियन और बी० एस० एफ० की दो बटेलियन मौजूद हैं । इन फोर्सेज के पहुंचने के बाद वहां जो फोर्सेज का डिप्लायमेंट किया गया इस तरह से किया गया कि जो बहुत सेंसेटिव एरियाज थे वहां पर ज्यादातर इन्हीं फोर्सेज को रखा गया और पी० ए० सी० को मुकामात से हटाया गया । लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने हाउस से जैसी अपील की है इसी संदर्भ में कल ही मैं कह चुका हूं । बेशक पी ए सी० के बारे में ऐसी शिकायत है लेकिन सारी की सारी पुलिस फोर्स को इस तरह से कंडम करना मुनासिब नही है । हम बराबर इस बात पर आमा है और हम इस पुलिस फोर्स की छानबीन करेंगे । उसमें जो गलत तत्व होंगे उनको हटाया जायेगा । इसके साथ-साथ जो रेक्रूटमेंट की नई पालिसी होगी उसमें क्रास सेक्शन आफ द सोसायटी को भर्ती किया जायेगा । इस संबंध मे सभी राज्य सरकारों को लिखा गया है । फिलहाल जहां कहीं भी इस प्रकार से कोई गड़बड़ है वहां सी० आर०पी एफ और० बी० एस० एफ० को तुरन्त भेज दिया जाता हैं ।

श्री शांति त्यागी : मैं मेरठ का निवासी हूं और मेरठ में वाया क्या है वह मैंने देखा है । मेरठ की स्थिति अब बिलकुल नार्मल है । आदरणीय प्रधान मंत्री जब वहां गई तब से वहां की पोजिशन बिल्कुल अच्छी हो गई है । प्रधान मंत्री जी का वहां गलियों-गलियों में स्वागत हुआ है जहा बहुत गरीब लोग रहते हैं । हम सब लोग उनके साथ थे । उनके लिए यह मुमकिन नहीं था कि घर-घर जायें लेकिन चाहे हिन्दू को चोट पहुंची हो या मुसलमान को वहां के उकादाकर मुलाकात में उन्होंने विजिट किया । मैं हाशमी जी से यह दर्खास्त करूंगा कि यह ऐसा मौका है जब मेरठ की पोजिशन नार्मल है......

श्री उपसभापति : : ठीक है । हो गया । (व्यवधान)

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभापति महोदय, मैं सिर्फ घर मंत्री जी से 'हां', या 'ना' में जवाब चाहता हूं। (व्यवधान) मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जितने भी कमीशन बने उनकी रिपोर्ट आपके पास आई। क्या आप आज सदन में यह कहने के लिए तैयार हैं कि आयन्दा जब कभी भी कोई दंगा नहीं होगा तो उस पर निश्चित रूप से कमीशन बैठाया जाएगा, आयोग बैठाया जाएगा ?

श्री जे० के० जैन : श्रीमन्, इस बात बात का मूल प्रश्न से क्या संबंध है ?

श्री लाडली मोहन निगम : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस आयोग की जैसी भी रपट आएगी, क्या वह सार्वजनिक रूप से देश के सामने रखी जाएगी ? आप सदन के सामने तो रखते हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : सदन के सामने रखने का मतलब देश के सामने हो गई।

श्री लाडली मोहन निगम : एक प्रश्न मैं यह भी करना चाहता हूं कि मेरठ के दंगों की रपट राज्य सरकार ने बनाई और वह आपके पास आई। इसलिए क्या आपका फर्ज नहीं होता है कि उसको आप सदन के सामने ही नहीं, बल्कि देश के सामने रखें ताकि उस रपट में जो सुझाव रखे गये हैं वे देश के सामने आएं ? इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह भी है कि क्या आप कोई निश्चित अवधि तय करेंगे कि जब कभी भी इस प्रकार के कमीशन बनाये जायें वे दो तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट देने के बाद उसमें जो दोषी पाये जाते हैं उन पर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए आप कोई अवधि निश्चित करें क्योंकि आज तक किसी को भी सजा नहीं हुई ताकि उस अवधि में दोषी व्यक्तियों को सजा दे दी जाय ? ये मेरे प्रश्न हैं . . . (व्यवधान)

श्री उपसभापति : आप अपने प्रश्नों को दोहराइये नहीं, उन्होंने सब नोट कर लिये हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपसभापति महोदय, मेरठ में हाल में जो दंगे हुए है उनके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक जुडिशियल कमीशन जस्टिस पारिख को नियुक्त किया गया है। उसकी सिफारिशें आने पर ही सब कुछ होगा। जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट दी है वह सिचुएशन रिपोर्ट है और इस सिचुएशन का जहां तक ताल्लुक है, खूब तफसील के साथ इस हाउस में मेरठ के दंगों के संबंध में पूरे दिन डिसकशन हो चुका है। ऐसी सूरत में इस रिपोर्ट के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है जो सदन को मालूम न हो और आयन्दा भी जहां कहीं इस प्रकार के खतरनाक दंगे होते हैं, आम तौर पर जुडिशियल कमीशन का रिवाज है और मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें उस पर चलेंगी। कल इसी सिलसिले में दूसरे सदन में मैंने कहा था कि जो लोग दंगों में इनवोल्व होते है उन पर केस चलाने के लिए नार्मल कोर्ट्स के बजाय स्पेशल कोर्ट्स बैठाना सरकार के विचाराधीन है और उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, may I know from the honourable Minister whether he is aware of the fact that the riots in Meerut and other places, particularly the riots in Meerut, have created an atmosphere in which the fundamentalism in both the communities is uncessarily being fanned by different elements? So, I would like to know whether the Government has any specific measure so that this fundamentalism can be curbed because of the secular character of this country and our long tradition. Sir, I find that in the rural areas this fundamentalism is assuming dangerous proportions and, in order to tackle this, the Government has to take firm

steps and has to categorically state what those steps are. In this connection, Sir, I want to know from the honourable Minister whether any memorandum was submitted by some Members of Parliament, belonging to a particular community, and whether the Government has taken any action on the grievances mentioned in that memorandum which include the barbarous behaviour of the para-military forces.

SHRI P. C. SETHI: Sir, the increase in the fundamentalism is a matter of concern for all of us and, apart from taking measures which are legal, it has to be curbed and fought on a basis which is both political and social and that requires the active support of not only the ruling party, but also of all the major parties because communal disturbances cause concern not only to us but also to you.

SHRI A. G. KULKARNI: The memorandum has been submitted by Members of Parliament belonging to a particular community.

SHRI P. C. SETHI: As far as the memorandum which has been submitted to the hon. Prime Minister by MPs and a few others is concerned, a group of persons have been appointed. A committee has been appointed by the Prime Minister, headed by me, and we are having a meeting of that group tomorrow.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Is it a group or committee?

SHRI P. C. SETHI: It is a committee—a group of persons forming a committee. *(Interruptions)* We are having a meeting tomorrow. My hon. colleague, Mr. N. D. Tiwari, is also there and there are other Members also. We would go point by point. We have had two discussions in this connection. A detailed discussion was held between a few hon. Members and the Prime Minister. Then they had another discussion with me. And, Sir, let me say that keeping in view the appointment of that committee and also the discussions which have taken place, in which Hashmi Saheb was also present, I am very happy that for the time being they have suspended the 'morcha'.

SHRI K. C. PANT: Sir, has compensation been paid to the riot victims of Meerut? The second question is that the Home Minister quite rightly stressed the importance of social and political workers in promoting communal harmony. The absence of riots is a negative aspect; communal harmony is a positive concept. In view of this, may I know whether he has made any assessment of the effectiveness of the Peace Committee and other such citizens' bodies which have been formed in Meerut, and if they have not been very effective, wheher he has any other proposal to involve such persons, so that in the long run communal harmony is ensured and not merely the avoidance of riots?

SHRI P. C. SETHI: In this connection, I would like to point out that apart from the National Integration Council which we have got at the Central level, we have requested the State Governments to have National Integration Councils in their respective States, which should in turn be extended to every district, and in every district important talukas should have a National Integration Council which would be a sort of permanent standing body to resolve this problem.

As far as compensation is concerned, Rs. 5000 from the State Government and Rs. 2000 from the Prime Minister have been paid; that means, in all Rs. 7000 have been paid to the deceased. Similarly, the injured persons have also been paid compensation to the tune of about 60,000. As far as property loss is concerned, property compensation is also in the vicinity of Rs. 1 lakh, which has been distributed. The loss of property is still more. But the other claims with regard to loss of property are still being examined.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Mr. Deputy Chairman, I go back to the original reply of the hon. Minister.

Somebody said that brevity is the soul of wit. But in summarising the situation report submitted by the Government of UP in a few sentences, the hon. Minister has wittingly or unwittingly introduced an element of inaccuracy, and also made it somewhat inadequate. The inaccuracy lies in that he has spoken of 'place of worship'. In fact, that is a controversial question, whether the particular structure which led to this trouble is a place of worship or not a place of worship. That matter is sub judice. He should have said 'alleged place of worship' rather than 'place of worship'. The inadequacy lies in that it hardly enlightens us on anything, specifically brought out by the hon. Minister. My specific question is about the role of PAC. I very much appreciate what the hon. Prime Minister has said that obviously in any force there are good elements and bad elements and the entire force should not be condemned by one stroke of pen. But, Sir, the attitude and behaviour of this particular force in U.P. is not something new; it has been known to us since 1972. We have received very detailed reports, eye-witness reports, about the butchery committed in broad day-light, which has led, for the first time in our country, to a writ petition to the Supreme Court asking the Supreme Court to issue a mandamus to the U.P Government to disband it. It has never been done before. There are also at least 12 writ petitions brought to my notice by individual citizens who have complained about the murder of their husbands or fathers or sons in broad day-light by the PAC, and on them also the Supreme Court has taken notice and taken action. Also, for the first time, again, Sir, a group of citizens of Meerut have sent a legal notice to the Government of UP saying that by virtue of actions, legal or illegal, by a force, by an instrument, by a machinery of the State so much loss of life has taken place and so much loss of property has taken place, and if the Government of UP does not compensate them duly, then they shall file civil suits against them. Therefore, Sir, the question of the PAC is somewhat different. We certainly wish to maintain the morale of our police force but we do not wish to maintain the morale of a criminal force in order that it may kill more people. Therefore, Sir, my question is this. The hon. Minister has very correctly said that in November itself he had sent an instruction to the Government of UP...

AN HON. MEMBER: Is he making a speech, Sir?

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Let me complete. In November itself he very correctly sent an instruction to the Government of UP to restructure the PAC. (*Interruptions*) This was reported to the meeting of the Committee on Communal and Caste Harmony of the National Integration Council on November 30, 1982. Now, three months have passed. I would like to know from the hon. Minister whether he has received any response, any report from the Government of UP about the progress in the implementation of the instructions sent by him as Home Minister.

SHRI P. C. SETHI: Sir, the first question which Shahabuddin Saheb has raised is that the UP Government have mentioned that there was a dispute between the members of the Hindus and the Muslims over a place of worship. Now his objection is to these words of place of worship. But, Sir, further it has been clarified by saying that the Hindus claimed that there was a Shiv Ling which was about 50 to 60 years old and the Muslims contended that it was installed recently. I have also said that the Muslims also claimed the existence of a mazar adjoining the piao at the spot which was denied by the Hindus. Therefore, in the details, it was clarified. (*Interruptions*) Please, let me reply. Sir, as far as the PAC's role is concerned, we have written to the U.P. Government to go into the subject thoroughly and find out the persons who are responsible for any such acts and spot them out and take action against them. **At the same time, Sir, I**

would like to point out that we have also said in the recent communication to the State Governments not only UP but also other State Governments that not only the Force has to be representative of all the cross-sections of the society but the entire training programme of the Force has also to undergo a change. Their attitudes have to change. They must be trained to handle the situation carefully. They must be trained to meet the problem and not indulge in any such acts which would bring a bad name to the police force as such. Therefore, all these things have been done, and apart from that....

SHRI SYED SHAHABUDDIN: What is the response of the UP Government?

SHRI P. C. SETHI: The UP Government has responded by saying that we are looking into the points which have been raised by you. And, Sir, I have said yesterday that with regard to particularly Bihar and UP, we would call a meeting of the Chief Ministers of both the States and discuss with them the entire question.

डा० (श्रीमति) नजमा हेपतुल्ला: जैसाकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बतलाया कि माइनार्टीज कम्युनिटीज के एम पी काफी तादाद में उनसे मिले थे और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनके साथ विचार-विमर्श हुआ। जो भी मेरठ में या और जगह फसादात होते हैं, इस बारे में यह बड़ी खुशी की बात है न सिर्फ उन्होंने हमारी बात सुनी बल्कि उस पर निर्णय लेकर एक कमेटी बनाई है जिसमें होम मिनिस्टर साहब, बूटा सिंह जी और हमारे सीनियर लोग हैं। Shahabuddinji, I did not disturb you and I would not like you to disturb me. मैं आपके जरिये से होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहती हूं कि जहां पर हम सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं वहां पर सरकार से दूसरा यह सवाल भी पूछना चाहते हैं कि जो कोई भी रायट हुए, अगर मैं मेरठ रायट की बात निकालूं तो उसके अन्दर क्या वह हमें यह बतायेंगे कि बहुगुणा जी जैसे नेता और शाही इमाम साहब या जो भी नेता हैं और दूसरे आर० एस० एस० और बी० जे० पी० के लोग क्या मेरठ गये थे और उन्हें क्या कोई ऐसी तकरीरें इश्तालअंगेज की थी जिससे बजाय इसके कि लड़ाई के अन्दर पीस की भावना आती, अमन का माहौल पैदा होता लड़ाई और बढ़ गयी। क्या इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी है और अगर है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया ?

SHRI P. C. SETHI: Sir, without blaming any particular party, it is a fact that sometimes the activities of RSS are such which are a cause for concern. Similarly, sometimes the Vishwa Hindu Parishad is also becoming a fundamental like organisation.

AN HON. MEMBER: Only sometimes.

DR. BHAI MAHAVIR: Was it there in Meerut?

SHRI P. C. SETHI: As far as Meerut is concerned, I would not like to blame any particularly party but it is a fact that some of the persons did go there to incite violence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now go to the next question. Yes, Shri F. M. Khan.

श्री सत्य पाल मलिक: श्रीमन्, मैं मेरठ का रहने वाला हूं एक सवाल (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now. I will pass on to the next question. We are having Calling Attention on the same subject. I request you to

resume your seat. You can then speak on the same subject.

श्री सत्यपाल मलिक : मैं बहुत कम वक्त में खत्म कर दूंगा एक प्रश्न... (व्यवधान) आप मुझे बराबर कहते रहे थे कि मैं इजाजत दूंगा। आप बराबर कहते रहे कि सवाल करने का मौका दूंगा। ..(व्यवधान) एक प्रश्न मुझे करने की इजाजत दें ...(व्यवधान) आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : देखिए मलिक जी, कालिंग अटेंशन भी है। इसमें 20 मिनट समय लग गया है और आपका उसमें नाम है... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक : मेरा नाम नहीं है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा ... (व्यवधान) मैं सिर्फ मेरठ के सवाल पर.. (व्यवधान) आपने मुझे बराबर आश्वासन दिया है। एक मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। मैं उस शहर का नहीं होता तो नहीं कहता। मैं कायदे की बात कहने वाला हूं इसलिए जिद कर रहा हूं।

श्री उपसभापति : आपका नाम कालिंग अटेंशन में मौजूद है।

श्री सत्यपाल मलिक : मैं उसमें नहीं बोल रहा हूं .... (व्यवधान)

श्री उपसभापति उसमें आप पूछ लीजिए...

Your name is in the Calling Attention you can ask the question then or you can ask in the next question. I will allow you in the next question.

श्री सत्यपाल मलिक : मैं वहां का रहने वाला हूं आप मेरी इतनी भावना को समझने की कोशिश करिये।

श्री उपसभापति : अगला क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप पूछ लीजियेगा।

श्री सत्यपाल मलिक : वह नहीं आयेगा

श्री उपसभापति : कैसे नहीं आयेगा, वह आ रहा है।

श्री सत्यपाल मलिक : मेरा निवेदन आप सुन लें ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The same question you can raise in the next question. Do not worry.

श्री सत्यपाल मलिक : आपके हाथ में है आप एलाऊ नहीं करेंगे ... (व्यवधान)

श्री उपसभापति : मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में एलाऊ कर रहा हूं। आप यही बात पूछियेगा जो आप पूछना चाहते हैं .. (व्यवधान)

No, I will not allow you now. We go to the next question now.

*63. [*The questioner (Shri F. M. Khan) was absent. For answer vide Col. 35-36 infra*]

Setting up of an Inter-State Council

*64. SHRI K. MOHANAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether Government propose to set up an Inter-State Council as envisaged in the Constitution of India in view of the increasing demand for more powers to States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): No, Sir.

SHRI K. MOHANAN: I was quite sure even when I put the question that the answer will be a big 'No.' But I want to ask the Government in what circumstances the framers of our Constitution have included such a provision in the Constitution. Sir, Dr. Ambedkar, when he was presenting the draft Constitution to the Constituent Assembly said that the framers of the Constitution are very specific on the subject that our Constitution must be a federal one at least in spirit, because he says that, so that it establishes a dual policy with the Union at the Cen-

tre and the States at the periphery, which are endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. The Union is not a league of States united in their loose relationship nor are the States the agencies of the Union. The Union and the States are created by the Constitution. Both derive their respective authority from the Constitution. One is not subordinate to the other. The authority of one is coordinated with that of the other. This is the spirit of our Constitution, and the framers of the Constitution were very specific to make it a federal one. In these circumstances I want to point out that two agencies are there, one in the field of political and administrative matters and other in the field of settlement of disputes between the Centre and the States, according to Article 263...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question now. All these things are known to the Minister. You put your question.

SHRI K. MOHANAN: I am putting the question. I have only given the background of the provision in the Constitution. And the provision of this Article is: "investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest;" In these circumstances, and in view of the fact that there have been demands from States and so many issues have arisen from the States like Punjab, Assam, Tamil Nadu Andhra, it is necessary, in my opinion, that there should be a Council as such, as envisaged in the Constitution. I don't understand the hesitation on the part of the Government.

SHRI P. C. SETHI: In this connection, first of all I would like to say that Article 263 is an enabling provision. It says: "If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council" charged with such and such duties, then the President will appoint such a Council. Secondly, I would like to say that this question was considered at great length and after consideration it was found that a single body would find it difficult to apply itself to the wide spectrum of problems, such as labour, law and order, health, taxes, national integration, planning, etc. It is unlikely that because of its very wide field of work the inter-State Council may be able to examine these subjects in sufficient detail. Such a body may also have to sit in session for a long time which the members may find it difficult, etc. So, it was recommended that the existing arrangements which are there, would be sufficient to meet the exigencies of the situation. The National Development Council is there; then there are other councils, like the National Integration Council, Zonal Councils, the Chief Ministers' Conference, the Finance Ministers' Conference, the Food Ministers' Conference, the Labour Ministers' Conference, Governors' Conference, Chief Secretaries and Home Secretaries and IGPs, Conference, the Central Council of Health, the Regional Councils for Sales Tax, the Central Council of local Self Government etc. Therefore, in view of this, it was considered that unless a need is felt to appoint such inter-State Councils, it is not desirable to enter into this venture at this particular juncture

SHRI K. MOHANAN: I think the NDC or the Zonal Council and other forums have nothing to do with such a Council of the States. It very clearly states here that this Council is intended to handle problems arising out of the relationship between the States and the Centre, NDC, we know, is handling only other problems; Zonal Council we know, is only a talking shop. There is no use of it. This is envisaged in the Constitution and the framers of the Constitution were so wise to foresee difficulties arising out of the CentreState relations. Why should there be this hesitation on the part of the Government in establishing such a body?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has already replied to it.

SHRI P. C. SETHI: I have already replied to it. But I would only like to add that recently, a new system has been developed. The Prime Minister herself has done this. On any important issue, for example, on the Assam question, on the Punjab question, not only the leaders of the Opposition have been involved in the talks in order to resolve the problem, but along with the Government nominees and leaders of the Opposition in Parliament, representatives of the State Governments concerned, Chief Ministers and leaders of the Opposition in the respective States have also been involved. Therefore, we are trying to evolve a solution to the problem through various methods.

SHRI ERA SEZHIYAN: I do agree with him that there are so many councils to go into these questions to go into questions and disputes between different States. But here is a constitutional provision which oempowers the Government to establish such a council.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has said that it is only an enabling provision.

SHRI ERA SEZHIYAN: An inter-State council, if it is formed, will have a Constitutional basis, whereas, these other councils do not have Constitutional sanction. This is particularly important because an inter-State council can be charged with the duty of enquiring into and advising upon disputes which may arise between States, investigating and discussing subjects in which some or all the States or the Union and one or more of the States have a common interest, making recommendations upon any subject and in particular recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject. Therefore, this is the idea behind it. If the hon. Minister aware that the Administrative Reforms Commission has itself made a strong recommendation on the establishment of an inter-State council and this recommendation has been made in the background of your zonal councils, NDC etc.? Therefore, when this is the background in which the recommendation has been made, I would like to know the Government's thinking in regard to the establishment of an inter-State Council, as per the Constitutional basis and on the basis of the recommendations of the Administrative Reforms Commission.

SHRI P. C. SETHI: What the hon. Member has read out is the detail which has been provided in article 263. As far as article 263 is concerned, I again say that this is only an ehabling provision and this gives the power to the President. It has been said here that it shall be lawful for the President by order to establish such a council. He has referred to the recommendation of the Administrative Reforms Commission. It is not only the recommendation of the Administrative Reforms Commission which is before the Government. There was this Setalvad Committee also. This Committee's recommendation is also there. The overall view has been which still prevails, that the present position is quite enough to tackle the problem. But in any case, article 263 can be made use of if any such situation arises.

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : माननीय उपसभापति जी, जिस समय यह फैसला हो गया कि संविधान का रूप क्वासी यूनीटरी, क्वासी फेडरल रहेगा और इससे सम्बन्धित धाराओं पर जब बहस हुई थी तो यह भी चर्चा हुई थी । बाबासाहेब अम्बेडकर को उन्होंने कोट किया है । उन का स्वयं यह विचार था कि केन्द्र बहुत शक्तिशाली हो, केन्द्र शक्तिशाली इस लिए हो कि डेवलपिंग सोसाइटी में यह अनिवार्य हो जाता है । उन्होंने यह भी कोट किया था कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 1935 में जितनी शक्तिशाली थी आजादी के बाद और ज्यादा शक्ति आती उसमें, और ज्यादा शक्तिशाली होती । इस सबके बारे में उनके क्या विचार थे, क्या गृह मंत्री इस बारे में बतायेंगे ?

SHRI P. C. SETHI: Hon. Shri Maurya has not asked any question, I am grateful to him for clarifying the position.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। उन्होंने संविधान की जो धारा पढ़ी है क्या उसका अर्थ यह है कि 'टु क्रिएट इन्टर-स्टेट काउंसिल सब्जेक्ट टु सेटिस्फेक्शन उस में सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन की बात है, जब सरकार और राष्ट्रपति महसुस करेंगे—'टु क्रिएट ए कांउसिल' यह स्पिरिट उसमें आप देख रहे हैं? binding on Government a way.

और क्या आपको इसका पता है कि कर्णाटक, त्रिपुरा, तमिनाडु और वैस्ट बंगाल ने इस तरह की कौंसिलें बना दी हैं। तो मैं यह जानकारी चाहूंगा कि सबका हवाला देकर आप जो बता रहे हैं उसका आप गलत इंटरप्रेटेशन कर रहे हैं और यह सही है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : किसी राज्य ने अपने यहां कोई कौंसिल बना ली हो, यह अलग बात है, लेकिन यह जो कौंसिल का सुझाव है, यह अखिल भारतीय स्तर की कौंसिल होगी और उसमें सदस्य होंगे : Prime Minister, Leader of the Opposition, Home Minister and one or two other Ministers plus one representative each of the Zonal Council. So, this is a question of appointing a Council on an all-India basis.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Launching of INSAT-IB

*63. SHRI F. M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to launch INSAT-IB in the near future; and

(b) if so, what are the details in this regard and by when it is likely to be launched?

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) INSAT-IB is a part of the INSAT-I System of geo-stationary satellites for delivery of satellite-based telecommunications, radio and TV and meteorological earth observation and data relay services. In all functional aspects, the INSAT-IB is identical to INSAT-IA. However, it incorporates certain hardware changes as a result of the experience gained from INSAT-IA, INSAT-IB will be launched from Cape Canaveral by US-NASA Space Shuttle onboard its eighth flight, in the third quarter of 1983.

Representation of Minority Communities in the C.R.P.F. and B.S.F.

*65. SHRI SYED SHAHABUDDIN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the U.N.I. report which appeared in the 'Statesman', dated the 28th January, 1983, to the effect that Government were making efforts to give more representation to Muslims and other minority communities in the C.R.P.F. and the B.S.F. to make them more broad-based;

(b) if so, what is the present level of representation of various minority communities in these forces which led Government to augment their recruitment; and

(c) what is the proposed level of representation which is considered due and adequate by Government?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI): (a) Government have seen the press report.

(b) and (c). Particulars as to Community-wise representation in CRPF and BSF are not required to be maintained. While adhering to the constitutional guarantee regarding equality of opportunity to all citizens, efforts are made to broad-base recruitment to Central forces so that their composition is representative of the cross-section of the society.